National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.multidisciplinaryjournal.org
ISSN: 2455-9040
Received: 14-05-2024, Accepted: 03-06-2024, Published: 29-06-2024
Volume 9, Issue 2, 2024, Page No. 57-59

बहुराष्ट्रीय निगमः चुनौतियाँ एवं समाधान

आसुराम डऊकिया
सहायक आचार्य, भुगोल विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बायतु, बालोतरा, राजस्थान, भारत

सारांश
भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रवेश गम्भीर विवाद का विषय बन गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगम लम्बें समय से कार्यरत है। 1991 के पूर्वतः बहुराष्ट्रीय निगम कुछ शर्तों के अधीन कार्य कर रहे थे। उस समय उन्हें अंश पूँजी में प्रमुख भाग की अनुमति प्रदान की गई। नई नीति से बहुराष्ट्रीय निगमों को कुछ क्षेत्रों में 51 प्रतिशत से भी अधिक पूँजी निवेश की अनुमति प्रदान की गई। नई नीति के अनुसार यदि किसी बहुराष्ट्रीय निगम का सम्पूर्ण उत्पादन निर्यात के लिए हो तो उसे शत् प्रतिशत पूँजी निवेश की अनुमति दी जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वव्यापीकरण की नीतियों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था को जीवन्त बनाने और उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वव्यापीकरण के सार्थक प्रयास निर्विवाद रूप से सफल रहे हैं। किन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अत्यधिक मनमानी करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए जिससे देश की सार्वभौमिकता को खतरा उत्पन्न हो।

मूल शब्दः अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, बहुराष्ट्रीय निगम, रोजगार, वैविक पूँजीवाद, प्रबन्धकीय तकनीकें, विपणन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार।

भारत के आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की विदेशी पूँजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निजी क्षेत्र की विदेशी पूँजी का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। अतः यह पूँजी ऋण एवं अनुदान के रूप में प्राप्त नही होती वरन् बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं निगमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सा पूँजी में भाग बंटाते विदेशी सहयोग अथवा पोर्ट–फोलियों निवेश के रूप में होता है। इस प्रकार निजी क्षेत्र की विदेशी पूँजी इन बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से सरकारी तथा गैर–सरकारी दोनों क्षेत्रों में लगी हुई है। भारत में इस तरह का विदेशी पूँजी निवेश कई विकसित देशों जैसे–अमेरिका, इंग्लैण्ड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि देशों की कम्पनियों एवं निगमों के द्वारा किया गया है।

बहुराष्ट्रीय निगम एक परिचय

साधारण बोलचाल में बहुराष्ट्रीय निगम का अभिप्राय एक ऐसी कम्पनी अथवा व्यावसायिक संस्था से है जिसका व्यवसाय अथवा उत्पादन तथा वितरण के क्रियाकलाप एक से अधिक देशों में फैले हुए है। आई.बी.एम. वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के अनुसार ''एक बहुराष्ट्रीय निगम वह है जो (1) अनेक देशों में कार्य करता है, (2) उन देशों में विकास, निर्माण एवं अनुसंधान का कार्य करता है, (3) जिसका बहुराष्ट्रीय प्रबन्ध होता है तथा (4) जिसका स्कन्ध स्वामित्व बहुराष्ट्रीय प्रबन्ध होता है।''
दूसरे शब्दों में संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ''बहुराष्ट्रीय निगम एक ऐसी कम्पनी या व्यावसायिक संस्था है जिसका व्यवसाय एवं कारोबार अपने जन्म स्थान के देश से बाहर अनेक देशों तक फैला होता है। ''यही कारण है कि ऐसे निगमों को बहुराष्ट्रीय कम्पनी या अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी/निगम अथवा ज्छब् के नाम से भी जाना जाता है।

बहुराष्ट्रीय निगम का भारतीय परिदृष्य

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में बहुराष्ट्रीय निगम एवं निजी पूँजी निवेश की देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं जहाँ एक ओर देश के प्राकृतिक साधनों के विदोहन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहाँ दूसरी ओर देश के औद्योगीकरण, विपणन, उन्नत प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीक के साथ–साथ अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा मिला हैं। भारत में विदेशी पूँजी निवेशों में वृद्धि हुई हैं तथा रोजगार बढ़ा है। प्रबन्धकीय क्षमताओं में वृद्धि हुई है। भारत सरकार द्वारा आर्थिक उदारीकरण व विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के प्रस्तावों के अनुमोदन काफी रहे है पर वास्तविक प्रवाह बहुत कम रहा है। विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं निगमों ने आधारभूत उद्योगों के विकास में पूँजी निवेश करने और जोखिम उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
विकासशील देशों में प्राकृतिक साधनों की प्राचुर्यता है पर टेक्नोलॉजी साहस, पूँजीगत सामान तथा प्रशिक्षित श्रम शक्ति के अभाव में इन प्राकृतिक साधनों का वांछित विदोहन नहीं हो पाया। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में ये सब साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा उन्होंने भारत जैसे कई विकासशील देशों के प्राकृतिक सम्पदा के विदोहन को सम्भव बनाया हैं भारत में खनिज सम्पदा के विदोहन को सम्भव बनाया हैं भारत में खनिज तेल की खोज तथा उसके विदोहन में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
बहुराष्ट्रीय निगमों के पास उत्पादन की उन्नत तकनीक होती है और वे अनुसंधान एवं विकास से प्रौद्योगिकी का विकास करते रहते है अतः विदेशी पूँजी निवेशों के साथ–साथ विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों की उच्च तकनीक भी आती है। भारत में पेट्रोलियम, रसायन, औषधि, तथा इन्जीनियरिंग एवं इलेक्ट्रोनिक उद्योगों में उच्च तकनीक प्राप्त हुई है। भारत जैसे विकासशील देशों में स्थानीय उद्योगपतियों में जोखिम उठाने का साहस बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति में बहुराष्ट्रीय निगम अपने विशाल साधनों एवं लम्बें अनुभव से नये उद्योगों की स्थापना में जोखिम उठानें में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। भारत के ऊर्जा टेलीकम्युनिकेशन, सड़क निर्माण, सौर ऊर्जा विकास आदि में बहुराष्ट्रीय निगम आगे आ रहे है। बहुराष्ट्रीय निगमों में कई शोध कार्य करने का सामर्थ्य होता है। और उनके शोध कार्यों का लाभ उनकी सभी देशों की शाखाओं एवं सहयोगी कम्पनियों को मिलता है। इससे भारत जैसे देशों को भी शोध एवं विकास के वे लाभ मिल जाते है जो अन्यथा संभव नही होते। बहुराष्ट्रीय निगमों का कार्य क्षेत्र बड़ा होता है। और उनके बड़े पैमाने की उत्पादन, वितरण एवं प्रबन्ध व्यवस्था में काफी लोगों को रोजगार मिलता है। उच्च प्रशिक्षण व्यवस्था से रोजगार के अवसर भी

बढ़ते है। आज भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों में कई भारतीय रोजगार में लगे हुए है। बहुराष्ट्रीय निगमों में उच्च प्रबन्ध कुशलता का लाभ भारत के उद्योगों को मिला है और भारतीय प्रतिस्पर्द्धा कम्पनियों ने अपनी प्रबन्ध कुशलता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता को बढ़ाया है।

भारत में विदेषी बहुराष्ट्रीय निगमों प्रमुख चुनौतियाँ

यद्यपि बहुराष्ट्रीय निगमों से देश के आर्थिक विकास एवं प्राकृतिक साधनों के विदोहन में मदद मिलती है उच्च प्रौद्योगिकी एवं उन्नत तकनीक का लाभ मिलता है। प्रबन्ध कुशलता में वृद्धि होती है और देश के लोगों को रोजगार मिलता है पर जब बहुराष्ट्रीय हितों की बलि दे देते है, विदेशी मुद्रा में हेरा–फेरी करते है और देश के उद्योगों को बाहर करते है तो उनके विरूद्ध आवाज बुलन्द होना स्वाभाविक है। बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैः–

- बहुराष्ट्रीय निगम तथा विदेशी निजी कम्पनिया विदेशी ब्राण्ड एवं ट्रेडमार्कों के उपयोग से ऊँची कीमतों द्वारा भारतीय उपभोक्ताओं का शोषण करते है और भारी लाभ अर्जित करते है। यह आकड़ों से उजागर होता है कि थोड़ी–सी पूँजी निवेश भी वे भारी लाभ अर्जित करते है।
- भारत में विदेशी निजी कम्पनियों एवं बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा जब बड़ी मात्रा में लाभ, रायल्टी, फीस विदेशों में भेजे जाते हैं तथा बड़ी मात्रा में निर्मित या कच्चा माल आयात किया जाता है जबकि निर्यात कम किया जाता है तो अन्ततः भुगतान सन्तुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- जहाँ विदेशी निजी पूँजी निवेश तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से सहयोग एवं सहभागिता उद्योगों के उन्नत प्रौद्योगिकी एवं उच्च तकनीक के लिए की जाती है वहाँ ये कम्पनियाँ विकसित देशों की छोड़ी हुई पुरानी टेक्नोलोजी को विकासशील देशों में स्थानान्तरण कर देती है, इससे जहाँ एक ओर ऊँचे दाम वसूल कर लिये जाते है, वही दूसरी ओर देश उन्नत प्रौद्योगिकी से वंचित रह जाता है। भारत में ऐसी धोखाधड़ी बहुत हुई और भारत को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। यह तकनीक देश के अनुकूल भी नही होती तो नुकसान होता है।
- बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अन्तरण कीमत से भारी लाभार्जन करती हैं। वे ऊँची अनतरण कीमत से भारी लार्भाजन करती है। वे ऊँची कीमतों पर अपनी विदेशी सहायक कम्पनियों से कच्चा माल खरीदती है। तब दूसरी विदेशी सहायक कम्पनियों को निर्मित माल बहुत कम कीमत पर बेच देती हैं जिससे बहुराष्ट्रीय कम्पनी का यहॉ तो उद्योग का लाभ घट जाता है पर विदेशों में बढ़ जाता है। यह करों की चोरी भी बढ़ाता है और देश को हानि उठानी पड़ती है।
- कई बार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जो अपने लाभ को अधिकतम करने के प्रयास में रहती है देश के हितों की उपेक्षा करती है। जो अन्ततः देश के भावी विकास में बाधा पहुंचाते हैं। यही कारण है कि कोका कोला तथा आई.बी.एम जैसी अमेरिकी कम्पनी को भारत में अपना कारोबार बन्द करना पड़ा था।
- बहुराष्ट्रीय निगम एवं कम्पनियाँ अपने विशाल आर्थिक साधनों एवं महंगे भ्रमात्मक विज्ञापन साधनों के द्वारा देश के उद्योगों के लिए कट्टर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते है, यहॉ तक की कभी–कभी अपने उत्पादों को घाटे में बेचकर भी अपनी प्रतिस्पर्द्धा कम्पनियों को बाहर कर देते हैं अथवा उन्हें अपने में मिलाने को बाध्य कर देते हैं अथवा उन्हें एकाधिकारी की स्थिति में पहुँचकर लाभार्जन का मौका मिलता है। इसके कारण देश के उद्योगपति आगे नहीं आ पाते। देश अपने औद्योगिक विकास के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर आश्रित हो जाता हैं जो कभी भी घातक हो सकता है।
- निजी क्षेत्र की विदेशी कम्पनियां अथवा बहुराष्ट्रीय निगम अधिकारिक लाभार्जन के उद्देश्य से किन्हीं खास–खास क्षेत्रों में ही उद्योग लगाते है जिससे पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नहीं हो पाने से क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाया मिलता है जो देश के हित में नहीं हो सकता।
- बहुराष्ट्रीय निगम अपने विशाल आर्थिक साधनों के जोर पर अपने व्यावसायिक हितों की अभिवृद्धि एवं रक्षा के लिए कभी–कभी राजनैतिक भ्रष्टाचार का सहारा लेते है। मोटी–मोटी रकमें रिश्वत के रूप में देकर अपने हित साधते है। इसके कई उदाहरण इन दिनों प्रकाश में आये है। ये बहुराष्ट्रीय निगम कई बार राजनैतिक हस्तक्षेप भी करते है।
- बहुराष्ट्रीय निगम जहॉ एक ओर अपने विशाल पूँजीगत साधनों और उच्च तकनीक की उत्पादन पद्धतियों से लागत घटाते है वही दूसरी ओर ये देश के छोटे उद्योगों से कट्टर प्रतिस्पर्द्धा कर उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल देते हैं भ्रमात्मक प्रचार तथा विदेशी ब्राण्ड़ों एवं ट्रेडमार्को का उपयोग कर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेते हैं इस कारण देश के छोटे–छोटे उद्योगों का पतन हो जाता है और देश अन्ततः अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों पर निर्भर हो जाता है। यह देश की आत्मनिर्भरता एवं सुरक्षा दोनों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं।

चुनौतियों का समाधान–सरकारी प्रयास एवं सुझाव

औद्योगिक विकास देश की आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितयों का दर्पण है। बिना राजकीय सहायता एवं प्रोत्साहन के औद्योगिक विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। इसलिए आज राज्य मनुष्य की संपूर्ण क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है एवं आर्थिक क्षेत्र में राज्य का व्यापक हस्तक्षेप वर्तमान शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है। इसलिए कहा जाता है कि उद्योग क्षेत्र मे राजकीय हस्तक्षेप आज के युग की व्यवस्था है और अहस्तक्षेप की नीति एक काल्पनिक विचारधारा है। भारत के उद्योगों के विकास में सरकार की भूमिका/राजकीय सहायता के प्रयास निम्नलिखित है।:–

- सरकार द्वारा देश में उद्योगों के विकास में सहायोग करने हेतु प्रांरभिक अवस्था में उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व बड़े उद्योगों जैसे लौहा एवं इस्पात उद्योग एवं जूट उद्योग आदि को संरक्षण प्रदान किया जाता था परिणामस्परूप उद्योगों आदि को संरक्षण प्रदान किया जाता था परिणामस्वरूप उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा हो जाती थी वर्तमान में सरकार द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग की पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- भारत सरकार देशी उद्योगों के विकास हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करती है। यह सहायता उद्योग को ऋण, अनुदान, पूंजी, एवं अंशों के अभिगोपन आदि के रूप में दी जाती है। इस दृष्टि से केंद्रीय एवं राज्य सरकारों ने देश के विभिन्न भागों में विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की है जैसे औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक, राजस्थान वित्त निगम आदि इसके अतिरिक्त सभी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त उद्योगों के लिए बाजार अध्ययन, लाभकारी अवसरों उधमियों की खोज प्रबन्धकीय शिक्षण प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सुविधाएं प्रदान करती है।
- सरकार विशिष्ट देशी उद्योगों के विकास हेतु पृथक से संबंधित नीति की घोषणा करती है जैसे कपड़ा नीति, औषधि नीति, चीनी नीति, कृषि नीति, दूरसंचार नीति आदि

परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में निश्चितता का वातावरण ही नहीं बना रहता है अपितु इन उद्योगों के विकास विस्तार को गति मिल रही है।

- लघु उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना एवं विकास में सहायता देने परम्परागत औद्योगिक नगरों से उद्योगों का विकेन्द्रीकरण एवं कुछ स्थानों पर उद्योगों का पूर्व नियोजित विकास करने की दृष्टि से सरकार औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करती है इसी प्रकार इन बस्तियों की स्थापना करती है इसी प्रकार इन बस्तियों में उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सस्ती दर में उपलब्ध करती है जैसे स्थान पानी–बिजली कच्चा माल बैकिंग एवं परिवहन सुविधा आदि।
- सरकार निर्मित व अर्द्ध निर्मित माल की क्रय नीति के अंतर्गत देशी उद्योगों के विकास में सहायता पहुंचती है उदाहरण के लिए औद्योगिक बस्तियां एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों की स्थापना व विकास के लिए सरकार आश्वासन देती है कि उनके द्वारा निर्मित व अर्द्धनिर्मित माल का एक निश्चित अवधि तक निर्धारित मूल्य पर वह निंरतर क्रय करती रहेगी यही उनके माल के निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने कुछ महत्वपूर्ण उद्योग में पूंजी की लागत को कम करने एवं निर्यात संवर्द्धन हेतु अनेक उद्योग को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- सरकार कर नीति के द्वारा भी उद्योगों के विकास में सहायता करती है इसके अन्तर्गत सरकार ऐसे ही उद्योगों को कर संबंधी विभिन्न छूट प्रदान करती है जिनका विकास सरकार चाहती है जैसे निर्यात उद्योग पिछड़े हुए क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना आयात को कम करने हेतु स्थापित उद्योग आवश्यक यंत्र सामग्री उद्योग आदि इसके विपरित जिन उद्योगों की देश को आवश्यकता नहीं है उन पर अधिक कर लगाकर उनके उत्पादन को सीमित करने का प्रयास किया जाता है।
- सरकार ने उद्योगों के विकास हेतु सार्वजनिक निजी क्षेत्र के संयुक्त साहस एवं स्वामित्व में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया है परिणामस्वरूप सरकारी नीतियों का कुशलता पूर्वक क्रियान्वयन होगा इसके अतिरिक्त सरकार को निजी उद्यमियों की कार्यकुशलता एवं प्रबंधकीय दक्षता का लाभ ही नहीं होगा अपितु निजी साहसियों को उद्योग स्थापित करने के लिए सरकारी पूंजी व मार्गदर्शन का लाभ भी प्राप्त होगा।

निष्कर्ष

भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका एवं उनकी संभावित चुनौतियों को दृष्टिगत करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देश में तीव्र आर्थिक विकास, उद्योगों के उत्पादन में उच्च प्रौद्योगिकी एवं तकनीक के प्रयोग, शोध एवं विकास आदि के लिए विशाल विदेशी पूँजीगत साधनों का प्रवाह आधुनिक खुली अर्थव्यवस्थाओं में आवश्यक हो गया है। देश में उद्योगों की उत्पादन लागत घटाने, उनके आधुनिकरण, कुशल प्रबन्ध तथा रोजगार वृद्धि के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों/निगमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः उनके कार्यकलापों पर देश की सुरक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कुछ प्रभावी नियंत्रण लगाये जाना उचित है। यही कारण है कि देश के आधारभूत क्षेत्रों–विद्युत उत्पादन, उर्जा विकास, टेलीकम्यूनिकेशन, सड़क एवं भारी इन्जीनियरिंग उद्योगों में विदेशी निजी पूँजी निवेश को प्रोत्साहन एवं अधिक सुविधाएं की नीति अपनाई जा रही है पर उन क्षेत्रों में जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है अथवा जिन उपभोग उद्योगों के विकास के लिए देश में ही साहस एवं साधन उपलब्ध है उनमें बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए छुट नही है। भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में विदेशी पूँजी निवेश की नीति को काफी उदार बनाया गया है ताकि आधारभूत क्षेत्रों में प्रत्यक्ष पूँजी निवेशों को पर्याप्त आधुनिकतम प्रबन्धकीय तकनीक तथा प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश में अंश पूँजी को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। विदेशी पूँजी एवं सहायता की देश को आवश्यकता है। इसलिए इसका उपयोग निश्चय ही किया जाना चाहिए, लेकिन इसको काम में लेने में कुछ दोष या हानियॉ या खतरें है। जिनका उल्लेख उपर्युक्त पंक्तियों में किया गया है। अतः विदेशी पूँजी एवं सहायता का उपयोग करते समय उसके संबंध मे आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि वह उचित नियन्त्रण में रहे, देश को हानि न पहुंचा सके और आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर कोई प्रभाव न डाल सकें।

सन्दर्भ सूची

1. Mathur, Vibha- Trade Liberalization and foreign Investment of India- 1991- 2001
2. Nayyar, Deepak – The Foreign Trade Sector, Planning and Industrialization in India, Oxford University, Press 1993
3. D'souza, V.L. –Foreign Trade and Economic Development, Dharwar : Karnatak Univertsity Press 1966
4. Sinha, A.K- New Economics Policy of India Restructuring and Liberalising the Economy for 21st Century Deep. & Pnb. in Delhi.
5. रूद्रदत एव के.पी.एम. सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चॉद एण्ड कं. नई दिल्ली।
6. मिश्रा, पूरी– भारतीय अर्थव्यवस्था हिमालया पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
7. भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, आगरा,।
8. आर्थिक समीक्षा – भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. भारत 2006 प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. योजना– प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
11. इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली।